प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
24.06.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार''

- 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ शुरू–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में ली शपथ।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग से प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश का किया आग्रह।
- केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बने राज्यसभा में सदन के नेता।
- प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में।

लोकसभा–शपथ

18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ। लोकसभा के नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव तक सदन की कार्यवाही चलाने में भर्तृहरि महताब की सहायता के लिए नियुक्त अध्यक्ष को पैनल की शपथ दिलाई गई। बाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल, जीतनराम मांझी, डॉ वीरेंद्र कुमार, किरेन रिजिजू, चिराग पासवान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। हिमाचल प्रदेश के चारों भाजपा सांसदों अनुराग सिंह ठाकुर, कंगना रनौत, सुरेश कश्यप और राजीव भारद्वाज ने भी इस दौरान लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली।

वित्त आयोग बैठक

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग से हिमाचल को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने आज शिमला में प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं और अन्य मुद्दों पर वित्त आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री

ने राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास व इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया, ताकि इन क्षेत्रों से स्थानीय लोगों का पलायन रोका जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, जिसके चलते हिमाचल को आपदा पूर्व प्रबन्धन व राहत कार्यों की दृष्टि से विशेष प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने आयोग को बताया कि पिछले वर्ष मॉनसून सीज़न में भारी बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान के एवज में केंद्र सरकार ने 9 हज़ार 42 करोड़ रुपये का भुगतान अब तक नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके कारण राज्य को हजारों करोड़ का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है और प्रदेश को अब तक इस नुकसान के लिए भी मुआवजा नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमाचल प्रदेश का राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है।

इस बीच 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविन्द पनगढ़िया ने राज्य की उपलब्धियों विशेषकर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की। अरविंद पनघड़िया ने बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न है और आपदाएं यहां समस्याओं को और अधिक बढ़ा देती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने ओपीएस लागू की है जिससे वित्तीय स्थिति पर असर हुआ है और इस पर भी विचार किया जाएगा। अरविंद पनघड़िया ने कहा कि हिमाचल सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्यों की हिस्सेदारी तय की जाएगी।

बैठक में उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चन्द्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने भी विचार साझा किए।

जे.पी. नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को राज्य सभा में सदन का नेता बनाया गया है। वे सदन के नेता के रूप में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता बनाए जाने पर प्रदेश भाजपा में खुशी की लहर है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री सिकंदर कुमार, बिहारी लाल शर्मा और त्रिलोक कपूर सहित अन्य नेताओं ने उन्हें राज्य सभा में

सदन का नेता बनाए जाने पर बधाई दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है।

महालेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चैडविक हाउस ने इतिहास बनते देखा है और भविष्य में इसे सार्वजनिक सेवा के प्रति हमारे अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में देखा जाना चाहिए। गिरीश चंद्र मुर्मू ने ज्ञान के भंडार और लेखा परीक्षकों की भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में संग्रहालय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चैडविक हाउस में स्थित संग्रहालय को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है जो सीएजी संस्था के विकास, उपलब्धियों व श्रेष्ठता के मानक बिंदुओं को दर्शाता है। गौरतलब है कि चैडविक हाउस शिमला में एक महत्वपूर्ण इमारत है जिसका समृद्ध और व्यापक इतिहास है। कार्यक्रम के दौरान सीएजी के लेखा परीक्षा सलाहकार, बोर्ड के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

नामांकन

प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में होने वाले उप–चुनाव के लिए अब कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद देहरा विधानसभा क्षेत्र में 5, हमीरपुर में चार जबकि नालागढ़ में 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रवक्ता ने बताया कि देहरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर और भाजपा के होशियार सिंह सहित निर्दलीय सुलेखा देवी, अरूण अंकेश सयाल और संजय शर्मा शामिल हैं। इसी तरह हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के आशीष शर्मा, कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा और निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार व नंदलाल जबकि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के.एल. ठाकुर और कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा सहित कुल 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर व नालागढ़ में दस जुलाई को मतदान होगा जबकि 13 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। उम्मीदवार 25 व 26 जून को दोपहर बाद तीन बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं।

अवकाश

इस बीच प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान के मद्देनजर इन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित

किया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस दिन इन क्षेत्रों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा। उन्होंने बताया कि पंजाब के जालंधर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिलों में सेवाएं दे रहे पंजाब के पंजीकृत मतदाताओं और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के चलते सिरमौर और शिमला में सेवाएं दे रहे उत्तराखंड के पंजीकृत मतदाताओं के लिए भी 10 जुलाई को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इन राज्यों में पंजीकृत मतदाता जो सरकारी, अर्ध–सरकारी और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हैं, उनके लिए भी विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा इन विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता जो अन्य स्थानों में काम कर कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान है।

अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मेले व त्यौहार हमारी लोक मान्यताओं, परंपराओं व संस्कृति को जीवंत बनाए रखने और इनके संवर्धन व संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कल सोलन के प्रसिद्ध शूलिनी मेले की तीसरी व अंतिम सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति व देव परंपरा देश–विदेश में विख्यात है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक संध्याओं के माध्यम से प्रदेश की लोक संस्कृति व लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है और बाहरी राज्यों से आने वाले कलाकार संस्कृति के आदान प्रदान में सहायक बनते हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे।

जयराम ठाकुर

पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के लोगों का पूरा सहयोग व आर्शीवाद मिल रहा है और भाजपा तीनों उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही है और बीते डेढ़ वर्ष में प्रदेश में विकास कार्य ठप्प हो गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने जनहित के मुद्दों की उपेक्षा की और सरकार तानाशाही व बदले की भावना से कार्य कर रही है। जीएसटी काउंसिल द्वारा कार्टन पर जीएसटी घटाने के लिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि इससे बागवानों को बहुत राहत मिलेगी।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि स्पीति उपमंडल में इस वित्त वर्ष में जनजातीय उपयोजना के तहत विभिन्न विकास कार्यों पर 40 करोड़ 60 लाख रूपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने आज स्पीति उपमंडल के मुख्यालय काज़ा में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं से आम लोगों को लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के अन्य क्षेत्रों की तरह ही जनजातीय क्षेत्रों में भी एक समान संतुलित विकास करने के लिए कृतसंकल्प है। जगत सिंह नेगी ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए कम समय अवधि के चलते इन कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा भी मौजूद रही।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ शुरू–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में ली शपथ।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग से प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश का किया आग्रह।
- केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बने राज्यसभा में सदन के नेता।

  और

- प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद कुल 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में।